

प्रेषक,
निर्मला श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

व० ह० मु० प्दा० ड० (निर्देश)

सेवा में,
निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

कार्यालय मु० का० ०४०
डायरी संख्या १७६
दिनांक ०९/०७/२०१५

०९-०७-१५
मु०-०१-३२

क्र.भं. (उ.नि.५)

०९-७-१५

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-२

लखनऊ : दिनांक: ०७ जुलाई, २०१५

विषय:- वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना (एस०सी०एस०पी०) हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी ३०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक ११८/खा०ग्रा०बो०/गु०नि०प्र०/ २०१५-१६, दिनांक २४-०६-२०१५ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-८३ के अन्तर्गत उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना के लिए प्राविधानित धनराशि ₹० ८,८०,०००.०० (₹० आठ लाख अस्सी हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त धनराशि ₹० ५,००,०००.०० (₹० पाच लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

- (१) उक्त प्रस्तर-१ में स्वीकृति धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-२/२०१५/बी-१-९२५/दस-२०१५-२३१/२०१५, दिनांक ३० मार्च, २०१५, एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (२) व्यय की तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- (३) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि शिविर का आयोजन प्रदेश के ऐसे जनपदों/तहसीलों/ब्लॉकों में किया जायेगा, जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लाभार्थियों की जनसंख्या/आबादी २५ प्रतिशत से कम न हो।
- (४) स्वीकृत धनराशि के व्यय का योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के मानकों व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (५) स्वीकृत धनराशि के व्यय का नियमानुसार प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (६) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उससे व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में योजना की गाइड लाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (७) योजना के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा।

२७३
९-७-२०१५

- १- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- २- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग/व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग होने की दशा में विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(9) स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही होगी। किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या - 83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग -आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय-27- अन्य सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण की शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र0-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,
(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

संख्या 2/2015/बी-1/59-2-2015 32(खा)/2009 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्तीय एवं लेखाधिकारी,, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण 30प्र0शासन।
- 7- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग3/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग1/नियोजन अनुभाग4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 10- एन0आई0सी0योजना भवन,लखनऊ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
N-Sw
(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।